भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †256

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

वन धन योजना

†256. श्री पी.पी. चौधरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में विशेषकर राजस्थान के पाली निर्वाचन क्षेत्र में कोई वन धन योजना केंद्र खोला है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादों का ब्यौरा क्या है और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की आपूर्ति और निधि संवितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कोई योजना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(डॉ भारती प्रविण पवार)

(क): जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत 6.12 है। (जनगणना 2011)

(ख) से (ङ): राजस्थान राज्य में, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड), जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1,44,803 लाभार्थियों से जुड़े 479 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को मंजूरी दी है। इन वन धन केंद्रों के लिए प्रशिक्षण सहित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)-राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ (आरटीएडीसीएफ), उदयपुर को कुल 7135.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। आज की तारीख तक राजस्थान राज्य में 101 वीडीवीके को उपकरण/टूलकिट प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान में पाली निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई वीडीवीके प्रस्ताव नहीं मिला है।

*****